

## राजस्थान की नई ड्राफ्ट टाउनशिप नीति

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में राजस्थान सरकार ने एक नई ड्राफ्ट टाउनशिप नीति और भवन उपनयिमों के साथ लोगों एवं सभी हतिधारकों से सुझाव आमंत्रित किये हैं।

### मुख्य बढि:

- नई ड्राफ्ट नीतिके अनुसार, डेवलपर अपने टाउनशिप में बेची गई इकाइयों के रखरखाव के लिये सात वर्ष की अवधितक उत्तरदायी होगा।
  - ये टाउनशिप केवल अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट क्षेत्रों में निर्मित किये जाएंगे, जो यह सुनिश्चित करेंगे कि उस क्षेत्र में सभी आवश्यक सुविधाएँ जैसे: जल और ऊर्जा सुविधाएँ सुलभ हों।
- नए भवन उपनयिमों के अनुसार, शहरों की आवासीय योजनाओं और कॉलोनियों में छोटे भूखंड पर ऊँची इमारत बनाने की अनुमति नहीं होगी।
  - 500 से 750 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र के भूखंडों पर केवल आठ मंजिला इमारतें ही बनाई जा सकेंगी।
  - शहरों में 2500 वर्ग मीटर से अधिक के भूखंडों पर ग्रीन बिल्डिंग या पर्यावरण-अनुकूल इमारतों का निर्माण अनिवार्य किया जा रहा है।
  - ग्रुप हाउसिंग, बहु-आवासीय इकाइयों में अब प्रत्येक इकाई के लिये एक कार पार्किंग की जगह छोड़ी होगी।